(ख) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों ने नमक उत्पादकों अथवा नमक पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। तथापि, नमक उपकर अधिनियम, 1953 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नमक उपकर नियम, 1963 में यह व्यवस्था है कि 10–100 एकड़ तथा 100 एकड़ से ऊपर के क्षेत्र में काम करने वाले नमक वर्क्स पर क्रमशः 1.75 रु० तथा 3.50 रु० प्रति मे० टन की दर से नमक उपकर लगाया जा सकता है। 10 एकड़ से कम क्षेत्र में काम करने वाले छोटे नमक विनिर्माताओं तथा निर्यात किये गये नमक को इस उपकर से छूट मिली हुई है।

Administrative and Accounting Manual for Marine Products Export Development Authority

572. SHRI L. K. DOLEY: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) the year in which the Marine Products Export Development Authority was set up;

(b) whether it is a fact that no administrative manual and accounting manual have so far been drawn up for the Marine Products Export Development Authority;

(c) the reasons therefor; and

(d) the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) The Marine Products Export Development Authority was set up in the year 1972.

(b) to (d). No administrative manual has yet been drawn up.

A Draft accounting manual has already been compiled by the Marine Products Export Development Authority.

The Marine Products Export Development Authority regulations published in the Gazette on 27-8-77 contain considerable information about service conditions and allied matters. M.P.E.D.A. has taken up the preparation of an Administrative Manual.

जोधपुर हवाई अड्डे पर जाने वाले लोगों और यात्रियों को होने वाली असुविधाएं

573. **श्री आर० डी० गट्टानी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों और उन्हें लेने या छोड़ने आने वाले लोगों को, हवाई अड्डे के सैनिक क्षेत्र में होने के कारण, होने वाली कठिनाइयां और असुविधाएं दूर की जायेंगी ; और

(ख) राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा इस हवाई अड्डे के लिए एक अन्य सड़क बना दिये जाने के बावजूद लोगों को यह कठिनाई कब तक सहन करनी होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). सिविल एन्क्लेव के निर्माण कार्य के अप्रैल, 1978 तक पूरा हो जाने की आशा है। जब नया सिविल एन्क्लेव चालू हो जाएगा तो स्थिति में सुधार हो जाएगा ।

छोटे तथा बड़े उद्योगों को बैंक ऋण

574. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे तथा बड़े उद्योग बैंक ऋणों की कमी के कारण अपना उत्पादन अभी तक नहीं बढ़ा पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिये ऐसे उद्योगों को ऋण देगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुपालित वर्तमान ऋण नीति में यह दिया गया है कि उत्पादन में सहायता करने के लिये यथा संभव सहायता प्रदान की जाये जबकि साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक ऋणों का दुरुपयोग न हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, बैंकों से यह कहा गया है कि वे उत्पादन, निवेश और निर्यात के लिये वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करें। इसके साथ साथ छोटे पैमाने के क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत व्याप्त छोटे पैमाने के एककों को अपने सावधिक ऋणों पर 12 प्रतिशत से अधिक ब्याज की दर न वसूल करें। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों में दिसम्बर, 1976 से दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के दौरान 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह नीचे दी गई सारणी से प्रकट होता है :

(करोड़ रुपयों में)

	दिसम्बर, 1976	दिसम्बर, 1977	वृद्धि राशि	वृद्धि प्रतिशत
छोटे पैमाने के उद्योग . .	1258	1589	331	26.3
मध्यम और बड़े उद्योग .	5383	5941	558	10.4
	6641	7530	889	13.4

Dilution of Share Capital by Sterling Tea Companies

575. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the sterling tea companies have agreed to dilute their share capital complying with the FERA;

(b) whether the sterling tea companies have decided to merge themselves into two groups and diversifying their activities; and

(c) what are the details and Government's response thereto?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) The Indianisation scheme of most of the sterling tea companies consists of a group of sterling tea companies merging into Indian companies formed for the purpose of taking over their existing Indian business. As of now, there are no proposals for the diversification of their activities.

(c) The indianisation proposals of the sterling tea companies are engaging the consideration of Government. In principle, Government have no objection to such method of Indianisation by sterling tea companies.